रविवारीय

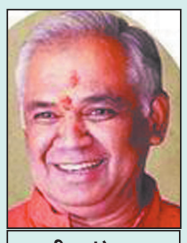

राजीव खंडेलवाल
(लेखक वरिष्ठ कर सलाहकार एवं पूर्व सुधार न्यास अध्यक्ष हैं)

पाकिस्तान की सऊदी अरब से रक्षा संधि

भारत की विदेश नीति ''चिंतित'' नहीं, बल्कि निश्चित! धरातल पर कितनी सही?

17 सितम्बर 2025 को रियाद में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रणनीतिक द्विपक्षीय रक्षा समझौता हुआ. यह स्वतंत्र पाकिस्तान के इतिहास की पहली औपचारिक रक्षा संधि है. यद्यपि चीन और अमेरिका जैसे देशों से पाकिस्तान को लंबे समय से सैन्य सहयोग मिलता रहा है, परन्तु कुएँ में कबूतर का भरोसा कहावत के अनुरूप पाकिस्तान ने औपचारिक सुरक्षा की गारंटी सऊदी अरब से पहली बार बन पाई है.

भारत-सऊदी के घनिष्ठ रिश्ते के बावजूद उक्त दुर्भाग्यपूर्ण संधि?- भारत और सऊदी अरब के रिश्ते सदैव सौहार्दपूर्ण रहे हैं. यही सऊदी अरब है, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (2016) और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह (2010) को सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज साश से अलंकृत किया था. जबकि पाकिस्तान का कोई भी शासक इस सम्मान से अब तक वंचित रहा है. ऐसे में यह रक्षा संधि भारत के लिए स्वाभाविक ही चिंताजनक और चौंकाने वाली है. क्योंकि संधि की शर्तों के अनुसार यदि किसी एक देश पर आक्रमण होने पर दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, तब दोनों संयुक्त प्रतिरोध करेंगे-सैन्य शक्ति सहित (क्या इसमें परमाणु क्षमता भी निहित है?). यह परमाणु बम की छत्र छाया एक तरफ सऊदी अरब के लिए इजराइल और दूसरी ओर पाकिस्तान के लिए भारत को इंगित करते हुए केंद्रित है? सऊदी अरब भलि-भांति इस बात को जानता है कि विश्व में भारत का दुश्मन नंबर एक कोई है, तो वह पाकिस्तान ही है. लगभग पांच महीने पूर्व ही पहलगाम में इसी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा 26 निर्दोष नागरिकों की महिलाओं के सामने नृशंस हत्या और 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई में भारत का ऑपरेशन सिंदूर इस संदर्भ को और अधिक गंभीर बनाता है. बावजूद इस तथ्य के कि ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ होने के तीन दिनों के भीतर ही पाकिस्तान को नाक रगड़कर भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील करनी पड़ी.

ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद पाकिस्तान का विश्व पटल पर बढ़ता कूटनीतिक प्रभाव- ऑपरेशन सिंदूर के समय केवल इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया. विपरीत इसके चीन, तुर्किये, अजरबैजान और मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़े रहे. तुर्की ने तो सैन्य साधन भी मुहैया कराए, जिसके विरोध में भारत में बहिष्कार तक की मुहिम चली. आश्चर्य यह कि विश्व के किसी भी देश ने पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम पहुंचने वाले पाकिस्तान को आतंकवाद-जनित भूमिका की आलोचना नहीं की.

पाकिस्तान ने इसी दौर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा संस्थानों से ऋण लेकर अपनी जर्जर अर्थव्यवस्था को संभालने की कुछ सफल कोशिश की. 26/11 मुंबई हमले जैसी वैश्विक आतंकवादी घटना के कारण पाकिस्तान की एक आतंकवादी देश के रूप में पहचान बनने के बावजूद अमेरिका की मदद से वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति का उपाध्यक्ष और अफगानिस्तान तालिबान पर प्रतिबंध समिति अध्यक्ष तक बन बैठा. दरअसल, पाकिस्तान की इस दोहरी नीति- 'एक ओर आतंकवाद का पोषण, दूसरी ओर आतंकवाद-रोधी मंच पर भागीदारी के बावजूद यह कूटनीतिक उसके लिए कैसे लाभकारी सिद्ध होती आई है, भारत के लिए यह शोध का

विषय होना चाहिए.

सऊदी-पाक रिश्तों की ऐतिहासिक जड़ें- सऊदी अरब पाकिस्तान का सदैव करीबी सहयोगी रहा है. पाकिस्तान को मान्यता देने वाले अग्रणी देशों में ईरान के बाद सऊदी आगे रहा है. 1960 के दशक में ही सऊदी ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया था. यमन युद्ध के समय पाकिस्तान ने सऊदी सीमाओं की रक्षा की. 1979 में मक्का की ग्रैंड मस्जिद कब्जे के दौरान पाकिस्तानी बलों ने निर्णायक भूमिका निभाई. 1971 के भारत-पाक युद्ध में भी सऊदी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था.

हाल ही में इजराइल द्वारा कतर (दोहा) में हमास नेताओं पर हवाई हमलों के बाद खाड़ी देशों का अमेरिका पर भरोसा कम हुआ है. शायद इसी कारण सऊदी को पाकिस्तान से औपचारिक रक्षा संधि करनी पड़ी है. संधि का एक निहित संदेश इजराइल के लिए है. यदि उसने सऊदी पर हमला किया, तो पाकिस्तान परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकता है. यही कारण है कि कुछ अतिवादी विश्लेषक इसे मुस्लिम देशों के सामूहिक सैन्य गठबंधन की शुरुआत मान रहे हैं. यदि अरब खाड़ी देश पाकिस्तान से इस प्रकार के समझौते करते गए तो क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम बम बनाने में सफल होगा? यह भारत के लिए निश्चित ही गंभीर सवाल है.

भारत की स्थिति और चुनौतियाँ- सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. लगभग 25 लाख भारतीय नागरिक वहाँ निवासरत हैं. ऐसे में यह संधि भारत के लिए केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक दृष्टि के साथ भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील है. यद्यपि सऊदी सरकार ने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि यह समझौता भारत-सऊदी संबंधों को प्रभावित नहीं करेगा, परन्तु इसे मासूम झूठ ही कहा जाएगा. क्योंकि यदि भारत पाकिस्तान-प्रेरित आतंक पर पाकिस्तान के विरूद्ध सैन्य अभियान छेड़ेगा (जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा में घुसकर मारा है यह दावा भारत ने लगातार किया गया था) सैन्य अभियान छेड़ेगा तो सऊदी का रुख संधि की शर्तों के अनुसार पाकिस्तान की ओर झुका हुआ हो सकता है, बशर्ते सऊदी भारत के साथ गरम जोशीले संबंधों को देखते हुए उक्त शर्त को मानने से इनकार कर पाकिस्तान के साथ विश्वासघात न कर दे? पर प्रश्न यह है कि क्या भविष्य में ऐसा हो पाएगा?

चिंताजनक तथ्य यह भी है कि भाजपा हो या कांग्रेस-भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस पर कोई सशक्त प्रतिक्रिया नहीं दी है. केवल कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इसे भारत की कूटनीतिक असफलता बताया है, और याद दिलाया कि पहलगाम हमले के समय प्रधानमंत्री मोदी स्वयं सऊदी अरब में मौजूद थे जो अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर तुरंत वापिस भारत लौटे. इस तथ्य को सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने संधि करते समय ध्यान में अवश्य रखा होगा?

अंतिम लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं?- क्या हम तथाकथित बुद्धिजीवी समालोचक/आलोचकों को इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए भारत में इस संधि पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं हुई है? इसका एकमात्र कारण क्या यह नहीं हो सकता है कि यह संधि सिर्फ दोनों राष्ट्रों पर हमला होने पर ही लागू होगी, हमला करने पर नहीं. मतलब जब पाकिस्तान पर हमला होगा, तभी संधि लागू होगी. भारत का शुरू से ही यह नीति रही है कि उसने कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान द्वारा हमला करने पर या आतंकी कार्रवाई के प्रत्युत्तर में ही सैन्य कार्रवाई की है. पाकिस्तान के लिए यह सिद्ध करना मुश्किल होगा कि भारत ने आक्रमण किया है. इसलिए हमें निश्चिंत होकर घोड़ा बेचकर होकर सो जाना चाहिए? हां इस संधि से भारत को एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि चीन की सैन्य ताकत और भारत के साथ लगातार चल रहे सीमावर्ती तनाव को देखते हुए भारत को भी विश्व में मित्र राष्ट्रों के साथ इसी तरह की रक्षा संधि करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए.

> सऊदी-पाक रक्षा संधि केवल एक द्विपक्षीय रक्षा करार नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति-संतुलन में बदलाव का संकेत भी है. भारत को यह समझना होगा कि पाकिस्तान धीरे-धीरे आतंकवादी छवि से बाहर निकलकर डिप्लोमेटिक खिलाड़ी बनता जा रहा है. अरब-खाड़ी देशों में बढ़ता पाक प्रभाव भारत की आर्थिक-सामरिक स्थिति के लिए चुनौती है. सबसे बड़ी चिंता यह कि भविष्य में यदि मुस्लिम सैन्य गठबंधन' मूर्त रूप लेता है, तो भारत की रणनीतिक स्थिति जटिल हो जाएगी. आखिरकार, इस संधि को भी वक्त के तराजू पर ही तौलना होगा.

व्यंग्य

हिन्दी भाषा का दिवस क्यों?

रवि उपाध्याय
लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

देश के एक बड़े वर्ग का दावा है कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा है. जबकि कुछ लोग कहते हैं कि वह राष्ट्र भाषा नहीं राज भाषा है. राष्ट्र भाषा और राज भाषा में ओहदे का विवाद हो सकता है,परंतु इसमे कोई विवाद नहीं है कि वह भाषा तो है और हम हर साल हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मानते हैं. शायद हिंदी दुनिया में ऐसी अकेली ऐसी भाषा है जिसका दिवस मनाया जाता है. कभी भी आपने अंग्रेजी दिवस, फ्रेंच दिवस आदि आदि भाषाओं के दिवस नहीं सुने होंगे. इससे पता चलता है कि हमारा देश अजूबों का देश है. यहां ऐसे ऐसे अजूबे होते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे.

आपने यह भी देखा होगा कि छोटे बच्चों और किशोरों के तीन तीन नाम होते हैं.घर में उन्हें टिल्लू, शेरू नाम से पुकारा जाता है, तो स्कूल का नाम अलग होता है और दोस्त -यारों के बीच सेंटी, हैरी जैसे ही कोई नाम होते हैं. उसी तरह भारत देश के भी अलग अलग नाम हैं.अंग्रेजी में इसे इंडिया कहा जाता है. राष्ट्रवादी इसे भारत के नाम से पुकारते हैं और जो खुद को सेक्युलर के सुरमा कहते हैं, वे इसे हिंदुस्तान कहते हैं. इसके अलावा भी आर्यावर्त भी हमारे भारत के ही नाम हैं. परंतु आर्यावर्त चलन में नहीं है. राष्ट्रवादी इसे भारत कहना पसंद करते हैं, तो कांग्रेस इसे इंडिया कहना सुनना पसंद करती है.

आपको एक बात और बता दें कि हिंदी भारत की प्रतिनिधि भाषा है. सभी भाषाओं में अकेली हिंदी और संस्कृत ऐसी भाषा है जिसने अपने सिर पर बिंदी धारण की हुई है.जबकि अंग्रेजी में केवल आई ही ऐसा अक्षर है जिसने अपने सिर पर बिंदी धारण की हुई है. मराठी भाषा में आई मां को कहा जाता है. इस तरह आई और मां दोनों पर बिंदी शोभायमान होती है. अब बात उर्दू और अरबी भाषा की तो इनमें बिंदी अक्षर के सिर पर नहीं बल्कि नीचे की तरफ होती है. इसे नुक़्ता कहा जाता है. यह भी एक रोचक तथ्य है कि उर्दू और अरबी ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें उल्टी दिशा में अर्थात राइट से लेफ्ट लिखी और पढ़ी जातीं हैं. हिंदी में बिंदी सनातन धर्म की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती सी प्रतीत होती है. सनातन धर्म में सुहागिन महिलाएं अपने मस्तक पर बिंदी लगातीं हैं. बिंदी जहां महिलाओं के सौंदर्य में वृद्धि करती है वहीं हिंदी भाषा में बिंदी भाषा के सौंदर्य में बढ़ोतरी करती है.

बता दें कि दुनिया में हिंदी एक मात्र ऐसी भाषा है जो सामने वाले की जल्दी ही समझ में वृद्धि कर देती है. जैसे व्यक्ति सामने वाले से कहता है कि हिंदी में समझाऊं क्या. वैसे ही उसकी प्रज्ञा जाग जाती है. वहीं अरबी-चीनी ऐसी हैं जो बोली भी जातीं और खाई भी जातीं हैं. जबकि अंग्रेजी ऐसी है जो बोलने के साथ पी भी जाती है. मेरे नादान मन में यह प्रश्न इसलिए उठा कि हिंदी तो आज़ादी मिलने के सदियों पहले से ही विभिन्न रूप (लोकभाषा) में बोली जाती है. इसलिए इसका कोई विशेष तिथि या तारीख हिंदी का बर्थडे या जन्मदिन नहीं कहा जा सकता. अब सवाल यह है की इसे मनाता कौन है? देश की 90 प्रतिशत आबादी तो आदी से अंत तक हिंदी ही बोलती है.आम जनता तो इसे कभी सार्वजनिक रूप से मानती नजर नहीं आती. इसे वहीं संस्थाएं मनाई जातीं हैं जो अनुदान जीवी है. हिंदी दिवस के नाम पर कुछ स्वनाम धन्य लोग इकट्ठा होते हैं.हिंदी विकास के नाम पर भाषण होते हैं.एक दूसरे को फूल मालाएं और शॉल अर्पित करते हैं. समोसा कचोरी उड़ाते हैं. चाय- चुई होती है, हिंदी दिवस की इस भावना के साथ इतिश्री हो जाती है. गणेश चतुर्दशी पर लगाए जाने वाले नारे की तर्ज कामना की जाती है कि हिंदी दिवस मोरिया अगले बरस तू लोकर आ.

वैसे भी मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वाक़ई हिंदी आज भी जीवित है. गैर हिंदी भाषी का सम्मान करते हैं. शाल दुशाला और सफेद चमकीली पन्नी में लपेटा नारियल (दर्शकों को ऐसा भान होता है कि वह चांदी जड़ा हो) भेंटकर उसे उपकृत करते हैं. उसके साथ अपना हंसता-मुस्कराता फोटू खिंचवाते हैं और फिर सरकार से अनुदान के नाम पर मोटा माल खींचते हैं. सम्मानित व्यक्ति भी सोचता है कि यह आयोजक पागल हैं या मैं भाग्यशाली हूं? इन सब को मालूम है कि 50 साल से यहां रहता हूं. हिंदी बोलता हूं. पढ़ता हूं. हिंदी की खाता हूं. हिंदी की पीता हूँ. अब पगले मुझे अपने से अलग क्यों समझ रहे हैं. हिंदी के विकास के नाम पर बने मंदिरों में जूते, चप्पल, साड़ियां और फर्नीचर बिकवा कर हिंदी के पंडे बने बैठे हैं. हिंदी के यह मंदिर सड़कों पर बनी उन मजारों के समान हैं जिन पर आते जाते लोग चिल्लर फेंक कर आगे बढ़ जाते हैं. इन मंदिरों में आने वाले अतिथि भी दान-दक्षिणा दे कर आगे बड़ जाते हैं.

मेरा मानना है कि हिंदी का अवसान आजादी के बाद धीरे-धीरे हुआ आजादी के नायक जो सत्ता में आए उन्होंने यह स्थापित किया कि हिंदी से श्रेष्ठ भाषा अंग्रेजी है. वह अनपढ़ जनता के सामने अंग्रेजी में भाषण ठोक कर अपना रुआब बुलंद करते थे. मजबूरी में हिंदी भी ऐसी बोलते थे कि आम जनता के ऊपर से निकल जाए. कहते हैं कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री ऐसी अंग्रेजी बोलते थे जो केवल अंग्रेजों के ही समझ में आती थी. वल्लभभाई इसलिए प्रधानमंत्री के लिए डिस्क्वालिफाई कर दिए गए कि उन्हें हिंदी आती थी. अंग्रेजी में उनका हाथ तंग था.

अब बात उनकी जो हिंदी के गर्भ से पैदा हुए. उसी की गोद में पले बढ़े और उसी मां को धता बता कर अंग्रेजी मेम से जी लगा बैठे. जी हां हम बात कर रहे हैं. हिंदी के अखबारों की. आजादी के 60 के बाद तक अंग्रेजी अखबारों का रूतबा तब की अभिनेत्री मधुबाला की तरह था.ऐश्वर्या राय से लेकर माधुरी दीक्षित तक के काल तक नेताओं और वामपंथी बुद्धजीवियों पर अंग्रेजी का नशा ऐसा ही था जैसा जनता पर उक्त हिरोइनों का नशा हावी था.

प्रो. विवेकानंद तिवारी
अध्यक्ष, आम्बेडकर पीठ एचपीयू, शिमला

मणिपुर में विकास और शांति की एक नई सुबह

मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मैतेयी और कुकी समुदायों के मध्य भड़की हिंसा से अब तक 260 लोग मारे जा चुके हैं तथा 60 हजार से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं. 14 अप्रैल 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए स्ञ का दर्जा देने पर सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था. इस आदेश के बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैला और हिंसा भड़की. कुकी पहले से स्ञ श्रेणी में है. उन्हें डर है कि अगर मैतेई को भी स्ञ का दर्जा मिला, तो वे पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे और इससे उनका सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा.

मणिपुर के इंफाल घाटी में लगभग 10% भूमि क्षेत्र है, जहां मैतेई बहुसंख्यक रहते हैं. बाकी 90% पहाड़ी इलाका कुकी और नगा समुदायों का है. यह क्षेत्र आदिवासी जमीन के अंतर्गत आता है और मैतेई यहां जमीन नहीं खरीद सकते.. कुकी समुदाय %कुकीलैंड% या %जूमलैंड% नाम से अलग प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं. मैतेई समुदाय और राज्य सरकार इस मांग को राज्य की अखंडता के लिए खतरा मानती है. कुकी समुदाय पर म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगता रहा है. सरकार ने भी कुकी पर अवैध अफीम की खेती की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया, जिससे सरकार के प्रति उनका अविश्वास और बढ़ गया.

कुकी का मानना है कि उनके समुदाय को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं. कुकी समुदाय का आरोप है कि मणिपुर सरकार (पूर्व भाजपा सरकार) मैतेई का पक्ष लेती है. वे सुरक्षाबलों और पुलिस पर भी एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हैं. इस संघर्ष के आरम्भ से ही भारत के सभी विपक्षी दल निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सरकार पर हमलावर थे, उनका एक ही प्रश्न था कि मोदी जी मणिपुर कब जाएंगे ? मणिपुर को लेकर संसद ठप

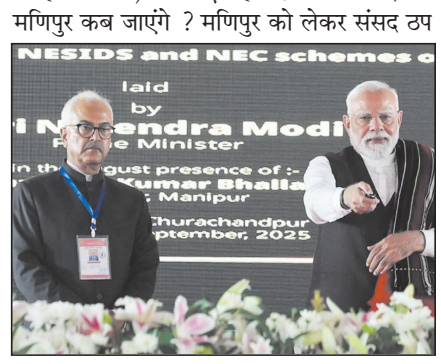

रखी गई. मणिपुर में महिलाओं पर हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया. सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की खंडपीठ ने मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां का दौरा किया. कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अन्य नेतागण अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए मणिपुर के हालातों को हथियार बनाते रहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी कई अवसरों पर मणिपुर पर अपनी चिंता व्यक्त की. विरोधी दलों के भारी दबाव के कारण भाजपा को अपनी ही सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा. अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मणिपुर दौरे से सभी को उचित उत्तर दे दिया है किंतु अब विरोधी दलों को इसमें रुचि नहीं रही क्योंकि उनका मणिपुर नैरेटिव फिलहाल समाप्त होता दिख रहा है. जिस समय भारत में मणिपुर हिंसा पर राजनीति चरम पर थी उस समय यूरोपीय संघ की संसद में मणिपुर को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ था जिसे केंद्र सरकार ने भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप बताते हुए खारिज कर दिया था अत: मणिपुर को लेकर कांग्रेस ने जो देश विरोधी वैश्विक नैरेटिव चलाया था वह भी अब ध्वस्त हो गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुकी बहुल हिंसा से सर्वाधिक प्रभावित चुराचांदपुर के लिए 7,300 करोड़ रुपए से अधिक और मैतेई बहुल इंफाल के लिए 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा करके यह संदेश देने का प्रयास किया कि सरकार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत उनके साथ है. प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर यात्रा के दौरान हिंसा पीड़ितों से भेंट करते हुए उन्हें सुरक्षा शांति तथा विकास का भरोसा दिया. अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मणिपुर को भारत की मणि बताते हुए कहा कि मणिपुर में उम्मीद और विश्वास की नई सुबह दस्तक दे रही है. किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति बहुत अनिवार्य है. आपसी संवाद और भरोसे से ही विवाद को समाप्त किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार मणिपुर के विभिन्न समुदायों के बीच आपसी संवाद, सम्मान और समझौते को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास रही है.

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पूर्व गृह मंत्रालय के लगातार प्रयासों के बाद दोनो समुदायों के बीच तनाव कम करने के काफी प्रयास किये है जिनका प्रभाव दिखाई पड़ने लगा है. लगातार चल रहे संवाद के कारण ही कुकी बहुल क्षेत्र से होकर निकलने वाला एनएच दो हाईवे अब पूरी तरह से खुल गया है और जनता व वस्तुओं की आवाजाही शुरू हो चुकी है. मणिपुर में अभी शांति के लिए कई अहम पड़ाव आने हैं. मैतेयी ओर कुकी समुदाय के बीच कुछ मतभेद अभी भी बरकरार हैं जिनको सुलझाने के प्रयास जारी हैं. इसमें कुकी समुदाय के लोग मणिपुर की छत के नीचे ही अपने लिए एक अलग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं फिर भी अब मणिपुर की समस्या का उचित समाधान निकलने की आस जग गई है.

प्रधानमंत्री मोदी ने विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद एक रैली को संबोधित किया जिसमें लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी जो मोदी -मोदी के नारे लगा रही थी. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जनसमुदाय मान चुका है कि प्रधानमंत्री मोदी के आने से मणिपुर में विकास और शांति लाने वाली एक नयी भोर हुई है.

और नदी लौट आई

सच्चे और निष्कलंक प्रेम की कथा- यात्रा

आयोजन

कार्यक्रम में नवभारत भोपाल के संपादक दिलीप झा हुए शरीक

साहित्यिक सरोकारों को जीवन्त करता हुआ और नदी लौट आई उपन्यास का भव्य लोकार्पण समारोह सम्राट अशोक अभियांत्रिकी संस्थान विदिशा में हिन्दी- दिवस 14 सितम्बर को सम्पन्न हुआ. आरंभ वक्तव्य में डॉ0 सुदीप शुक्ल ने संपूर्णता से उपन्यास पर चर्चा करते हुए उसके भाषा - प्रवाह, संवाद- शैली और रोचकता पर भी प्रकाश डाला.

उपन्यास लेखिका डॉ. कमल चतुर्वेदी ने कहा कि यह उपन्यास कहीं अपने ही करीब से पुकारती ज़िन्दगी की ही कथा है. जीवन मूल्यों के लिये संघर्षरत नारी की यह प्रणय-कथा प्रेम की अवधारणा को मूर्त रूप देती हुई, वर्तमान के दरकते प्रेम सम्बंधों को यह संदेश भी देती है, सच्चे और एकनिष्ठ प्रेम की सफलता में कोई संदेह नहीं होता है.

हिन्दी लेखिका संघ की पूर्व अध्यक्ष डॉ0 कुंकुम गुप्ता ने उपन्यास को समर्पण और संघर्ष की प्रेरणादायी कथा निरूपित किया. इस मौके पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि नवभारत के प्रखर संपादक दिलीप झा ने उपन्यास पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि जातिगत संकीर्णताओं में जकड़े समाज के लिये प्रेरणा-स्त्रोत यह उपन्यास पाठकों के मन में स्थायी प्रभाव उत्पन्न करता है. उन्होंने कहा कि नायिका रुचिरा अपने द्वंद और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ तले ऐसे दब जाती है कि वह अपने जीवन के खुशियों के पल को एहसास करना भी भूल जाती है. समाज के लोगों यह उपन्यास पढ़ना चाहिए. वहीं, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशान्त चौबे ने उपन्यास को पुनर्मिलन और पुनर्वास की सशक्त रचना निरूपित किया. इस अवसर पर विदिशा जिले के लोकप्रिय कलैक्टर अंशुल गुप्ता ने कहा कि उपन्यास को पढ़ते हुए हर्ष, विषाद, विश्वास और सच्चे प्रेम के उदात्त भावों की अनुभूति होती है. वहीं, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बरकतउल्ला विश्व विद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर एस. के.जैन ने उपन्यास को सरल, सहज, मार्मिक और मन को छू लेने वाला बताया. इसमें समाज में बदल रहे रिश्ते को जबरदस्त तरीके से रेखांकित किया गया है. ऐसे उपन्यास से समाज को प्रेरणा मिलती है.

अध्यक्षीय उद्बोधन में विदिशा के जाने माने पुरातत्वविद् गोविन्द देवलिया ने सभी गणमान्यों के वक्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए उपन्यास को सामाजिक चेतना जगाने वाला सफल उपन्यास बताया. हिन्दी दिवस के अवसर पर सभी वक्ताओं ने हिन्दी की दशा और दिशा पर अपने सर्वथा मौलिक और सारगर्भित विचार व्यक्त किये. मंच संचालन डॉ0 दीप्ती शुक्ल ने किया. विदिशा के साहित्यिक सरोकारों की संस्था प्रेरणा-मंच का यह आयोजन लेखिका को शुभकामनाएँ देते हुए संपन्न हुआ.